



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262910  
CG-DL-E-05052025-262910

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947

No. 1970]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2025

**का.आ. 2014(अ).—** जबकि मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड आवेदक ने, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एनटीपीसी आरईएल, ई3, इकोटेक-II, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306 पर स्थित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत एनटीपीसी आरईएल को खावड़ा आरई पार्क, गुजरात में अपनी 1555 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए पीएसएस2 से केपीएस2 तक 400 केवी एस/सी ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी फाइल संख्या 25-17/18/2023-पीजी दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत एनटीपीसी आरईएल को खावड़ा आरई पार्क, गुजरात में अपनी 1555 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए पीएसएस 2 से केपीएस 2 तक 400 केवी एस/सी ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 23.11.2024 और गरवी गुजरात (हिन्दी में) दिनांक 22.11.2024, तथा भारत के साप्ताहिक

राजपत्र दिनांक 14.12.2024 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, ने दिनांकित 01.04.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- एनटीपीसी आरईएल पूलिंग स्टेशन 2 - केपीएस2 400 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावर पर) लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारिषण लाइनें राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँवों	तहसील	जिला	राज्य
खावड़ा में आर.ई. पार्क	भुज	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो कि टेलीग्राफ प्राधिकरण को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजनों के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों को लगाने के संबंध में है, जो उपर्युक्त लाइन लगाने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, अर्थात:

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारिषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/ मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं.

838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

[फा. सं. 25-16/32/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

## MINISTRY OF POWER

### ORDER

New Delhi, the 29th April, 2025

**S.O. 2014(E).**— Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at NTPC REL, E3, Ecotech-II, Udyog Vihar, Greater Noida, Uttar Pradesh-201306 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 to NTPC REL for laying of 400 kV S/C Overhead Line from PSS2 to KPS2 for its 1555 MW Solar Power Project at Khavda RE Park, Gujarat.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No.25-17/18/2023-PG dated 11.09.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to NTPC REL for laying of 400 kV S/C Overhead Line from PSS2 to KPS2 for its 1555 MW Solar Power Project at Khavda RE Park, Gujarat.

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Times of India (in English) dated 23-11-2024 & Garvi Gujarat (in Hindi) dated 22-11-2024, and in Weekly Gazette of India dated 14.12.2024 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 01.04.2025 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s NTPC Renewable Energy Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. NTPC REL Pooling Station 2 - KPS2 400 kV S/C line (on D/C tower)

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Villages	Tehsil	District	State
RE Park at Khavda	Bhuj	Kutch	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NTPC Renewable Energy Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s NTPC Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/32/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)